प्रश्न– **5वीं अनुसूची के कार्यान्वयन में न केवल जनजातीय क्षेत्रों को संरक्षण दिया है, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न करने का अवसर भी उत्पन्न किया है। क्या आप इस विचार से सहमत है? तर्क सहित उत्तर दें।**
(200 शब्द)

The implementation of the 5th Schedule has not only provided protection to tribal areas bu has also created an opportunity to create dissatisfaction in the tribal areas. Do you agree with this. Answer with arguments. (200 words)

मॉडल उत्तर

दृष्टिकोण:
- भूमिका में 5वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करें।
- पैरा चेंज करते हुए बताएं कि 5वीं अनुसूची किस प्रकार जनजातीय क्षेत्रों को संरक्षण दिया है।
- अगले पैरा में बताएं कि किस प्रकार 5वीं अनुसूची ने जनजातीय क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न करने का अवसर भी उत्पन्न किया है।
- अंत में संतुलित निष्कर्ष दें।

संविधान के 5वीं अनुसूची में जनजातियों के क्षेत्र को शामिल किया गया है। जैसे- छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्यप्रदेश आदि। यह कहा जा सकता है कि 5वीं अनुसूची से इन क्षेत्रों को संरक्षण प्राप्त हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों के प्रशासन को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से मुक्त कर राज्यपाल के अधीन किया गया है।

- राज्यपाल 'जनजाति सलाहकार परिषद' की सलाह से इन क्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ाता है। इस परिषद में 75% सदस्य जनजातियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं।
- राज्यपाल द्वारा इन क्षेत्रों में संसद द्वारा अथवा विधानसभा द्वारा बनाएं गए किसी कानून को जो इन क्षेत्रों के विकास को दुष्प्रभावित करता है, लागू होने से रोका जा सकता है अथवा संशोधन कर लागू किया जा सकता है।

हालांकि जनजातीय क्षेत्र में 5वीं अनुसूची ने असंतोष उत्पन्न करने का अवसर भी उत्पन्न किया है।

- जनजातीय सलाहकार परिषद की भूमिका अधिक प्रभावी नहीं रही है। परिणामस्वरूप राज्यपाल के द्वारा इन क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में प्रभावी निर्णय लेने में बाधाएं उत्पन्न हुई है।
- 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिये जो कानून बनाये गये हैं, उन कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव रहा है। ऐसे भी अवसर आये हैं, जब इन कानूनों का दुरूपयोग किया गया है।
- वन कानून जैसे कानूनों के कार्यान्वयन ने जनजातियों को आजीविका के पारंपरिक साधनों से वंचित कर दिया है और वैकल्पिक साधन के निर्माण पर अधिक बल नहीं दिया गया है।